(c) Ministry of Rural Areas and Employment (Department of Rural Development) is the Nodal Ministry for framing the National Policy and guidelines for rehabilitation and resettlement of displaced persons.

Panel to Study Ground Water Level

1849. SHRI V.P. DURAISAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have appointed a penal to study ground water availability in the country; and

(b) if so, the details there of along with their objectives?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) and (b) The Government have not appointed any Panel to study ground water availability in the country. However, a Committee was constituted by the government in November, 1995 to review the methodology for estimation of ground water resources. The recommendations of the Committee which were finalised in June, 1997 were accepted by the government and all ground water organisations of the States were, advised to make estimation of ground water resources on the basis of revised methodology.

Central Assistance for Tista Barrage Project

1850. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) details of the Central assistance so far granted for Tista Barrage Project in West Bengal;

(b) break-up indicating the grant and loan components separately with interest rate in the case of loan;

(c) whether additional Central assistance of Rs. 150 crore had been approved during Eighth Plan;

(d) if so, the amount released during eighth Plan; and

(e) estimated cost of the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) to (e) At present first sub-stage of Stage I of Phase I of Tista Barrage Project with latest estimated cost of Rs. 1177 crores is under construction. Planning Commission released a special Central Assistance of Rs. 5 crores in the year 1983-84, an advance plan assistance of Rs. 10 crores in 1986-87 and Rs. 10 crores during 1987-88. Further, during VIII Five Year Plan an amount of Rs. 150.00 crores was provided by the Planning commission as additional Central Assistance for this project. Also during last three years the project was provided Central Loan Assistance under Accelerated Irrigation Benefits Programme amounting to Rs. 5.0, Rs. 15.00 and Rs. 10.00 crores respectively. The interest rate is prescribed by the Ministry of finance on year to year basis.

Financial Outlay for Godavari

1851. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any estimate been formulated by the Central Water commission on the financial outlay required to utilise atleast 75% of the water flow in the river Godavari;

(b) if so, the details of minimum cost at current prices to achieve 75% water utilisation of the river Godavari;

(c) have these plans been discussed at any significant level with the States; and

(d) if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

बाण सागर परियोजना

1852. **श्री मनोहर कान्ता ध्यानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि सोन नदी से संबंधित "बाण सागर परियोजना" उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मध्य त्रिपीक्षीय सहमति से वर्ष, 1973 में शुरू की गई थी,

(ख) क्या नदी-जल के बंटवार के लिए कोई आयोग बनाया गया था और क्या उक्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को वर्ष 1993 में प्रस्तुत कर दिया था, और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्णय न किए जाने के क्या कारण हैं तथा सरकार इस पर कब तक निर्णय करने का विचार रखती हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) बाण सागर परियोजना 1978 में शुरू की गई थी।

(ख) भारत सरकार द्वारा 1980 में गठित सोन नदी आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदी बेसिन की कुल जल क्षमता (योल्ड) भी दर्शाई गई थी।

(ग) सभी बेसिन राज्यों के सहमत न होने के कारण अतिरिक्त जल के आबंटन के बारे में निर्णय नहीं लिया जा सका।

चंबल जल परियोजना का निर्माण

1853. **श्री चुन्नी लाल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आगरा की वाह तहसील में चंबल नदी पर "चंबल जल परियोजना" निर्माणाधीन हैं,

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना की स्वीकृति हेतु मध्य प्रदेश की सहमति मांगी गई हैं क्योंकि चंबल नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी हैं जो दोनों से हो कर बहती हैं,

(ग) क्या यह सच हैं कि जो क्षेत्र इस परियोजना द्वारा सिंचित होगा, उस क्षेत्र में सिंचाई की कोई अन्य व्यवस्था व्यवहार्य नहीं हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता हैं । केन्द्र सरकार सिंचाई परियोजनाओं के लिए केवल तकनीकी और निवेश स्वीकृति देती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने "चम्बल जल परियोजना" नाम से कोई परियोजना स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं की हैं । तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत "चम्बल लिफ्ट योजना", उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच अन्तर राज्यीय पहलुओ का समाधान न होने के कारण स्वीकृत नहीं की गई हैं।

बाण सागर परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को लाभ

1854. **श्री चुन्नी लाल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सरकारों के बीच कनहर परियोजना पर बाणसागर समझौता हुआ था, यदि हां, तो उपरोक्त समझौते के अन्तग्रत उत्तर प्रदेश द्वारा कितना जल उपयोग किया जाना हैं,

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कनहर नदी पर प्रस्तावित बांध बनाये जाने की परियोजना निर्माणधीन हैं, और

(ग) यदि हां, तो बांध के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोपाल) : (क) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सितम्बर, 1973 में हुए बाणसागर परियोजना समझौते के अनुसार, उत्तर